International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बिहार राज्य में बालिका शिक्षा की स्थिति-परिस्थिति: बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनाओं के संदर्भ में बालिकाओं के हाशिएकरण, बहिष्करण और समावेशन का अध्ययन

जयनाथ चौधरी

पीएच.डी. शोधार्थी शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश

बिहार, जो कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान की वैश्विक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था, आधुनिक भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक विरोधाभासी स्थिति प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से, बिहार का सामाजिक ढाँचा गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जातिगत स्तरीकरण और सामंती मानसिकता द्वारा परिभाषित किया गया है। इन संरचनाओं ने पारंपरिक रूप से महिलाओं को घरेलू दायरे तक सीमित रखा और शिक्षा को लड़कों के विशेषाधिकार के रूप में देखा। हालांकि, 21वीं सदी के पहले दो दशकों में, बिहार ने एक आदर्श बदलाव (Paradigm Shift) देखा है। राज्य सरकार ने यह पहचाना कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है; सामाजिक संकेतकों, विशेष रूप से बालिका शिक्षा/महिला साक्षरता और लिंगानुपात में सुधार के बिना, राज्य की प्रगति अधूरी रहेगी। जिसके लिए राज्य सरकार ने कई प्रोत्साहन और कल्याणकारी योजनाओं की पहल भी की, इसी संदर्भ में यह शोध अध्ययन बिहार में बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन केवल नामांकन और साक्षरता के आँकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उन जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं की जाँच करता है, जो बालिकाओं को स्कूल से दूर धकेलती हैं (बहिष्करण) या उन्हें स्कूल तक खींचती हैं (समावेशन)। इसकी पूर्ति के लिए यह अध्ययन उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) का व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास करता है। और अंत में, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बिहार में बालिका शिक्षा की स्थिति में पिछले दो दशकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। राज्य सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और नवीन योजनाओं ने लड़कियों को हाशिए से उठाकर स्कूल के प्रांगण तक जरूर पहुँचाया है। तथापि, समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य अभी भी कोसो दूर है।

मुख्य शब्द: बालिका शिक्षा, प्रोत्साहन योजना, सीखने के परणाम, हाशिएकरण, बहिष्करण, समावेशन

परिचय: सामाजिक-ऐतिहासिक संदर्भ और शोध की रूपरेखा

बिहार, जो कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान की वैश्विक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था, आधुनिक भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक विरोधाभासी स्थिति प्रस्तुत करता है। 2011 की जनगणना और हालिया सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के अनुसार, बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक है। लगभग 127 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या (NITI, 2025) के साथ, यह राज्य भारत की जनसांख्यिकी का एक बड़ा हिस्सा धारण करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अनुपात

युवा और किशोर जनसंख्या का है। इस विशाल मानव संसाधन के केंद्र में "बालिका" (Girl Child) स्थित है, जिसकी शिक्षा और सशक्तिकरण न केवल राज्य के विकास के लिए अनिवार्य है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, बिहार का सामाजिक ढाँचा गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जातिगत स्तरीकरण और सामंती मानसिकता द्वारा परिभाषित किया गया है। इन संरचनाओं ने पारंपरिक रूप से महिलाओं को घरेलू दायरे तक सीमित रखा और शिक्षा को लड़कों के विशेषाधिकार के रूप में देखा। लड़कियों को "पराया धन" मानने की सांस्कृतिक अवधारणा ने उनकी शिक्षा में निवेश को हतोत्साहित किया, क्योंकि इसे "अनुत्पादक" माना जाता था। विवाह को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता था, और दहेज प्रथा के भय ने परिवारों को शिक्षा के बजाय विवाह के लिए संसाधन संचित करने के लिए विवश किया। हालांकि, 21वीं सदी के पहले दो दशकों में, बिहार ने एक आदर्श बदलाव (Paradigm Shift) देखा है। राज्य सरकार ने यह पहचाना कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है;
सामाजिक संकेतकों, विशेष रूप से महिला साक्षरता और लिंगानुपात में सुधार के बिना, राज्य की प्रगति अधूरी रहेगी।

शोध अध्ययन का उद्देश्य: इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार में बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण करना है। यह अध्ययन केवल नामांकन और साक्षरता के आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उन जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं की जाँच करता है, जो बालिकाओं को स्कूल से दूर धकेलती हैं (बहिष्करण) या उन्हें स्कूल तक खींचती हैं (समावेशन)। विशेष रूप से, हम राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजनाओं - जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना, और पोशाक योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन हाशिए पर स्थित समुदायों - महादलित, अल्पसंख्यक (विशेषकर मुस्लिम), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के अनुभवों को केंद्र में रखेगा, जो अक्सर मुख्यधारा की विमर्शों में अदृश्य रह जाती हैं।

शोध अध्ययन की पद्धति: यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data) के व्यापक विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4 और 5), एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE+), असर (ASER) रिपोर्ट, और विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी शोध पत्रों के निष्कर्षों को संश्लेषित किया गया है। हम "हाशिएकरण" (Marginalization) को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो न केवल आर्थिक गरीबी से, बल्कि जाति, धर्म, लिंग और भूगोल के अंतर्विरोधों से भी निर्धारित होती है।

बिहार में बालिका शिक्षा की स्थिति-परिस्थिति

बिहार में बालिका शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए, हमें साक्षरता, नामांकन, उपस्थिति और सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) के आँकड़ों का सूक्ष्म परीक्षण करना होगा। ये आँकड़े न केवल वर्तमान वास्तविकता को दर्शाते हैं, बल्कि पिछले दशकों में हुए परिवर्तनों की कहानी भी कहते हैं।

साक्षरता और जनसांख्यिकीय लाभांश: बदलती तस्वीर

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत 73% से काफी कम थी। इसमें भी लैंगिक अंतराल (Gender Gap) चिंताजनक था, पुरुष साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता मात्र 51.5% थी (NITI, 2025; NHSRC, 2021)। इसका अर्थ था कि राज्य की लगभग आधी महिला आबादी निरक्षर थी। यह सांख्यिकीय तथ्य बिहार के विकास की कहानी में एक बड़ा रोड़ा था।

हालांकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के ताजा आँकड़े एक आशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। NFHS-5 के अनुसार, बिहार में 6 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला आबादी का "कभी स्कूल जाने" (Ever attended school) का

प्रतिशत 56.9% (NFHS-4) से बढ़कर 61.1% हो गया है (IIPS, 2021)। यद्यपि यह वृद्धि अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है, लेकिन यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी की लड़कियाँ पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक संख्या में शिक्षा प्रणाली में प्रवेश कर रही हैं। शहरी और ग्रामीण विभाजन यहाँ स्पष्ट है; शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता और स्कूल जाने की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है (Parmar et al., 2025)।

लिंगानुपात में सुधार भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। NFHS-5 के आँकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल लिंगानुपात 1090 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गया है, जो 2015-16 में 1062 था (IIPS, 2021)। यह जनसांख्यिकीय बदलाव इस बात का संकेत है कि "बेटी बचाओ" जैसे अभियानों और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनों का कुछ असर हुआ है। अधिक लड़कियाँ जीवित बच रही हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि आने वाले वर्षों में स्कूलों में लड़कियों की संख्या में और वृद्धि होगी, जिसके लिए राज्य को अपनी बुनियादी ढाँचागत तैयारी को मजबूत करना होगा।

नामांकन, ठहराव और ड्रॉपआउट की गतिशीलता

बिहार की शिक्षा प्रणाली का एक विचित्र पहलू यह है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन लगभग सार्वभौमिक (Universal) हो चुका है, लेकिन जैसे-जैसे हम शिक्षा की सीढ़ी चढ़ते हैं, लड़कियों की संख्या तेजी से घटती जाती है।

UDISE+ 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर बिहार का सकल नामांकन अनुपात (GER) 64.9% है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का GER (66.8%) लड़कों (63.1%) से अधिक है (Jha, 2021)। यह एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय उलटफेर है। परंपरागत रूप से, लड़के शिक्षा में आगे रहते थे। यह परिवर्तन संभवतः राज्य सरकार की उन आक्रामक नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ दिया है। साइकिल योजना और पोशाक योजना ने लड़कियों के लिए स्कूल जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बना दिया है।

लेकिन यह सफलता की कहानी अधूरी है। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) पर आते ही एक भारी गिरावट (Sharp Drop) देखी जाती है। उच्च माध्यमिक स्तर पर GER गिरकर 35.9% रह जाता है, जिसमें लड़कियों का अनुपात 36.2% है (Jha, 2021)। इसका अर्थ है कि कक्षा 10 पास करने वाली लगभग आधी लड़कियां कक्षा 11 में नहीं पहुंच पातीं। ड्रॉपआउट दरों का विश्लेषण और भी चिंताजनक है। बिहार में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर लगभग 25.6% है, जो राष्ट्रीय औसत (~14.1%) से काफी अधिक है (Sharma, 2025)।

ड्रॉपआउट के अंतर्निहित कारण:

1. बाल विवाह का दबाव: यद्यपि कानूनी उम्र 18 वर्ष है, लेकिन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15-17 वर्ष की आयु विवाह के लिए "उपयुक्त" मानी जाती है। जैसे ही लड़की यौवन (Puberty) प्राप्त करती है, उसकी "सुरक्षा" और "इज्जत" को लेकर परिवार की चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जो अक्सर उसकी पढ़ाई छुड़ाकर शादी करने पर समाप्त होती हैं।
2. माध्यमिक विद्यालयों की दूरी: हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय (High School) नहीं है। जब स्कूल गाँव से दूर होता है, तो सुरक्षा कारणों से माता-पिता बेटियों को भेजने से कतराते हैं।

3. शैक्षिक विफलता और गुणवत्ता: ASER रिपोर्टें लगातार बताती हैं कि कई बच्चे बुनियादी पठन और गणित कौशल के बिना ही उच्च कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। जब पाठ्यक्रम कठिन हो जाता है (विशेषकर 9वीं के बाद), तो वे पढ़ाई के दबाव को झेल नहीं पाते और फेल होकर स्कूल छोड़ देते हैं (Parmar et al., 2025; Baig, 2024)।

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) और गुणवत्ता का संकट

नामांकन बढ़ाना एक बात है, लेकिन क्या बच्चे वास्तव में सीख रहे हैं? ASER 2022 और 2023 की रिपोर्टें बिहार के संदर्भ में एक गंभीर "लर्निंग क्राइसिस" (Learning Crisis) की ओर इशारा करती हैं। यद्यपि 2018 से 2022 के बीच सरकारी स्कूलों में उपस्थिति में मामूली सुधार (56.5% से 59.3%) हुआ है, लेकिन पढ़ने और गणित की क्षमता चिंताजनक है (ASER, 2022)।

विशेष रूप से, ASER 2023 "Beyond Basics" सर्वेक्षण ने 14-18 आयु वर्ग के युवाओं के कौशल का आकलन किया। निष्कर्ष बताते हैं कि लड़कियाँ बुनियादी व्यावहारिक कार्यों में लड़कों से पीछे हैं। उदाहरण के लिए, नक्शा पढ़ने, समय बताने या सरल वित्तीय गणना करने में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में कमजोर रहा (Bhattacharjea, 2024)। यह कौशल अंतराल (Skill Gap) भविष्य में उनके रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता की संभावनाओं को सीमित करता है। यह प्रश्न उठाता है कि क्या स्कूल केवल "मिड-डे मील" और "साइकिल वितरण केंद्र" बनकर रह गए हैं, या वे वास्तव में सशक्तिकरण के केंद्र हैं?

राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाएँ: नीतिगत हस्तक्षेप और सामाजिक अभियांत्रिकी

बिहार सरकार ने यह महसूस किया कि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर किए बिना बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसलिए, सरकार ने "सशर्त नकद हस्तांतरण" (Conditional Cash Transfer - CCT) और "वस्तु हस्तांतरण" (In-kind transfers) के मॉडल पर आधारित कई योजनाएँ शुरू कीं। इन योजनाओं ने बिहार को एक "कल्याणकारी राज्य" (Welfare State) के मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना: सामाजिक क्रांति के पहिए

2006-07 में शुरू की गई 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' संभवतः स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सफल और चर्चित हस्तक्षेपों में से एक है। इस योजना के तहत, कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक छात्रा को साइकिल खरीदने के लिए एकमुश्त राशि (शुरुआत में ₹2000, अब ₹3000) दी जाती है (Sumanlata & Kumari, 2024)।

योजना का दर्शन और तंत्र: इस योजना का मुख्य उद्देश्य "दूरी की लागत" (Distance Cost) को कम करना था। ग्रामीण बिहार में, हाई स्कूल अक्सर गांवों से 3-5 किलोमीटर दूर होते थे। पैदल जाना असुरक्षित और थकाऊ था। साइकिल ने इस दूरी को कम कर दिया।

प्रभाव का अकादमिक मूल्यांकन: अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन और निशीथ प्रकाश (2017) ने इस योजना का गहन प्रभाव मूल्यांकन किया। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे:

- नामांकन में वृद्धि: इस योजना ने माध्यमिक स्कूल में लड़कियों के नामांकन में 32% की वृद्धि की और लैंगिक अंतराल (Gender Gap) को 40% तक कम किया (Muralidharan & Prakash, 2017)।
- बहिष्करण में कमी: प्रभाव उन गांवों में सबसे अधिक देखा गया जो माध्यमिक विद्यालय से अधिक दूरी पर स्थित थे। इसने सिद्ध किया कि भौतिक दूरी वास्तव में एक प्रमुख बाधा थी।

- स्पिलओवर प्रभाव (Spillover Effect): साइकिल ने केवल नामांकन नहीं बढ़ाया, बल्कि इसने मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या में 18% और उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या में 12% की वृद्धि की (Muralidharan & Prakash, 2017)।

सामाजिक प्रभाव: साइकिल योजना ने बिहार की सड़कों का दृश्य बदल दिया। समूहों में साइकिल चलाती हुई लड़कियाँ न केवल अपनी शिक्षा के लिए स्कूल जा रही थीं, बल्कि वे पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दे रही थीं, जो महिलाओं को घर की चारदीवारी में रखते थे। इसने उन्हें "दृश्यता" (Visibility) और "आत्मविश्वास"प्रदान किया। यह योजना अब कई अन्य राज्यों और यहां तक कि जाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों के लिए भी एक मॉडल बन गई है (Pandey et al., 2025)।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY): जीवन चक्र दृष्टिकोण

सरकार ने महसूस किया कि केवल स्कूल स्तर पर हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या, कम उम्र में विवाह और उच्च शिक्षा में कम भागीदारी आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" शुरू की गई, जो बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक उसका साथ देती है।

योजना के प्रमुख प्रावधान (2025 के अद्यतन अनुसार):

- जन्म पर: ₹2000 (संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए)।
- टीकाकरण: 1 वर्ष और 2 वर्ष पूर्ण करने पर क्रमशः ₹1000।
- इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण: अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 (पूर्व में ₹10,000)। यहाँ "अविवाहित" शब्द महत्वपूर्ण है। यह राज्य द्वारा परिवारों को एक सीधा संदेश है: "शादी टालो, पैसा लो" (MKUY, 2025)।
- स्नातक उत्तीर्ण: ₹50,000 (पूर्व में ₹25,000) (MKUY, 2025)।

प्रभाव और चुनौतियाँ: इस योजना ने उच्च शिक्षा में लड़कियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किया है। कॉलेज परिसरों में लड़कियों की भीड़ अब एक सामान्य दृश्य है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ हैं:

- भुगतान में देरी: "मेधासॉफ्ट" (Medhasoft) पोर्टल और विश्वविद्यालय स्तर पर सत्यापन में देरी के कारण, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में अक्सर 2-3 साल लग जाते हैं। स्नातक पास करने के बाद आगे की पढ़ाई (जैसे - पीजी या बीएड) के लिए जिस समय पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह तब नहीं मिल पाता।
- तकनीकी बाधाएँ: आधार लिंकिंग, बैंक खाता मिसमैच और सर्वर की समस्याएं ग्रामीण लड़कियों के लिए एक बड़ी बाधा हैं, जिन्हें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए साइबर कैफे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

पोशाक योजना और छात्रवृत्ति: डीबीटी बनाम आपूर्ति का द्वंद्व

बिहार सरकार कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को पोशाक (Uniform) और पाठ्य पुस्तकों के लिए राशि प्रदान करती है। पहले यह राशि नकद दी जाती थी या स्कूल के माध्यम से कपड़े दिए जाते थे। बाद में इसे पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में बदल दिया गया।

- वर्तमान स्थिति (2024-25): शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) ने अपने नीति में बदलाव करते हुए, फिर से सिली-सिलाई पोशाक का रंग निर्धारित कर समान रंग के पोशाक (Readymade Uniforms) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और इसके लिए 20 जनवरी, 2025 को विद्यालयों के लिए एक आदेश भी जारी किया। इसके पीछे तर्क यह है कि अभिभावक

DBT की राशि का उपयोग अक्सर अन्य घरेलू जरूरतों (राशन, कर्ज चुकाना) के लिए कर लेते थे और बच्चे बिना वर्दी के स्कूल आते थे। अब जीविका दीदियों (स्वयं सहायता समूहों) या केंद्रीकृत एजेंसियों के माध्यम से वर्दी आपूर्ति की जा रही है।

- विश्लेषण: यह नीतिगत "यू-टर्न" (U-turn) राज्य की क्षमता और अभिभावकों की एजेंसी के बीच के तनाव को दर्शाता है। नकद हस्तांतरण ने भ्रष्टाचार (बिचौलियों) को कम किया था, लेकिन इसका "उद्देश्यपूर्ण उपयोग" (End-use) सुनिश्चित करना कठिन था। नालंदा जिले में किए गए अध्ययन बताते हैं कि बैंकिंग समस्याओं के कारण कई दलित परिवारों को पैसा मिला ही नहीं, या मिला भी तो उन्हें पता नहीं चला (Deeksha, 2023)।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): समावेशन का साधन

सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू की गई यह योजना अब समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उन ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय खोलना है, जहाँ

महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लिंग अंतराल अधिक है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को लक्षित करती है।

- बिहार में स्थिति: भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या – 1691 का जवाब देते हुए, 10 मार्च, 2025 को बताया कि बिहार में लगभग 595 KGBV संचालित हैं, जिनमें 30,000 से अधिक SC/ST लड़कियाँ नामांकित हैं। इन विद्यालयों को अब कक्षा 12 तक (टाइप-IV) उन्नत किया जा रहा है (PAB minutes, 2025)।
- चुनौतियाँ: ऑडिट रिपोर्टें (CAG, NITI Aayog) बताती हैं कि कई KGBV में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बाउंड्री वॉल, सुरक्षित भवन, बिस्तर और गुणवत्तापूर्ण भोजन की समस्याएँ आम हैं। शिक्षकों की कमी और सुरक्षा गार्डों का अभाव लड़कियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। फिर भी, अत्यंत गरीब परिवारों के लिए, जहाँ दो वक्त का भोजन भी मुश्किल है, KGBV उनकी बेटियों के लिए एकमात्र सहारा है (Krishnan, 2020)।

हाशिएकरण और बहिष्करण: सामाजिक वास्तविकता की परतें

सरकारी योजनाओं की सफलता के बावजूद, बिहार में बालिकाओं का एक बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा से वंचित है या हाशिए पर है। यह बहिष्करण एकरूपी नहीं है; यह जाति, धर्म और भूगोल के जटिल ताने-बाने से बुना हुआ है।

महादलित बालिकाएँ: संरचनात्मक हिंसा और शिक्षा

बिहार सरकार ने 2007 में 22 अनुसूचित जातियों को "महादलित" के रूप में वर्गीकृत किया, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक पिछड़ी थीं। इनमें "मुसहर" समुदाय सबसे प्रमुख है, जो परंपरागत रूप से कृषि मजदूर और चूहा पकड़ने वाले रहे हैं।

- मुसहर बालिकाओं की स्थिति: मुसहर समुदाय में महिला साक्षरता दर राज्य में सबसे कम है। यूनिसेफ (2025) और अन्य शोध बताते हैं कि मुसहर लड़कियाँ बाल श्रम और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हैं। जब माता-पिता ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, तो बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाती है (Singh et al., 2025)।

- **विद्यालय में भेदभाव:** सामाजिक बहिष्करण का सबसे क्रूर रूप स्कूलों के भीतर देखने को मिलता है। अध्ययनों में पाया गया है कि दलित और महादलित बच्चों को अक्सर "अछूत" माना जाता है। उन्हें कक्षाओं में सबसे पीछे बैठाया जाता है, मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) के दौरान अलग बैठाया जाता है, या शिक्षकों द्वारा अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। "गंदे रहते हो," "पढ़कर क्या करोगे" जैसी टिप्पणियाँ उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं और अंततः ड्रॉपआउट का कारण बनती हैं (Jayshree Bajoria, 2014; Kalaiselven & Maheswari, 2014)।

मुस्लिम लड़कियाँ: पहचान और गरीबी का संघर्ष

बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है, लेकिन सीमांचल के जिलों (किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार) में यह अनुपात काफी अधिक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को उजागर किया था, और बिहार के संदर्भ में यह स्थिति और भी गंभीर है।

चुनौतियाँ:

- **गरीबी और संसाधन:** बिहार के 33% मुस्लिम गरीबी रेखा से नीचे हैं (राष्ट्रीय औसत 22% से अधिक)। सीमित संसाधनों में, परिवार बेटों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं (Fatima, 2024)।
- **स्कूलों की अनुपलब्धता:** मुस्लिम बहुल गांवों में उच्च विद्यालयों की भारी कमी है। माता-पिता अपनी किशोर बेटियों को दूर के स्कूलों में भेजने से डरते हैं, विशेषकर वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक माहौल में जहाँ सांप्रदायिक तनाव एक चिंता का विषय हो सकता है (Aasha Khosa, 2025; Yasmin & Roy, 2024)।
- **मदरसा बनाम आधुनिक शिक्षा:** यद्यपि राज्य सरकार मदरसा बोर्ड को मान्यता देती है और आधुनिकीकरण का प्रयास कर रही है, लेकिन मदरसों से निकलने वाली लड़कियों के लिए मुख्यधारा की उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।

डिजिटल डिवाइड: नया असमानता क्षेत्र

COVID-19 महामारी ने शिक्षा में तकनीक की भूमिका को बढ़ा दिया है, लेकिन इसने एक नई तरह की असमानता को भी जन्म दिया है। ASER 2023 "Beyond Basics" रिपोर्ट बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक चौंकाने वाला "डिजिटल जेंडर गैप" दिखाती है।

- **स्मार्टफोन स्वामित्व:** 14-18 आयु वर्ग के 43.7% लड़कों के पास अपना स्मार्टफोन है, जबकि केवल 19.8% लड़कियों के पास यह सुविधा है (Baig, 2024)।
- **उपयोग की क्षमता:** ईमेल का उपयोग करने, ऑनलाइन फॉर्म भरने या जानकारी खोजने में लड़कियाँ लड़कों से काफी पीछे हैं।
- कारण: यह केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण का मामला है। परिवारों को डर है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट लड़कियों को "बिगाड़" देगा, उन्हें बाहरी दुनिया के संपर्क में लाएगा जिससे "प्रेम प्रसंग" या "विवाह-पूर्व संबंध" बन सकते हैं। इसलिए, तकनीक तक पहुंच को जानबूझकर प्रतिबंधित किया जाता है (Bhattacharjea, 2024)।

बुनियादी ढाँचागत बहिष्करण (Infrastructural Exclusion)

स्कूल का भौतिक वातावरण स्वयं एक बहिष्करण का कारक बन जाता है।

- शौचालय: UDISE+ 2023-24 के अनुसार, 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय हैं (Thakore, 2025)। लेकिन क्या वे उपयोग योग्य हैं? जमीनी रिपोर्टें बताती हैं कि कई शौचालय बंद पड़े हैं, गंदे हैं, या उनमें पानी नहीं है। माहवारी के दौरान, लड़कियों

के पास घर पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है (Ratan & Tiwari, 2025; Bihar's School of Shame, 2025)।

- चारदीवारी/बाउंड्री वॉल: 2023 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार के 90% प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उचित बाउंड्री वॉल नहीं थी (Singh et al., 2025)। एक खुली सीमा वाला स्कूल माता-पिता, विशेषकर लड़कियों के माता-पिता, के लिए असुरक्षा का कारण बनता है। आवारा जानवरों और असामाजिक तत्वों का प्रवेश स्कूल के माहौल को खराब करता है।

समावेशन की रणनीतियाँ: सरकारी और सामाजिक प्रयास

चुनौतियों के बावजूद, राज्य सरकार ने समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी रणनीतियाँ अपनाई हैं।

जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting)

बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से है, जिसने 2008-09 में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य के कुल बजट का एक निश्चित हिस्सा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण पर खर्च हो।

- विश्लेषण: 2022-23 में, कुल बजट का लगभग 18.1% महिलाओं के लिए आवंटित किया गया था (Sumanlata & Kumari, 2024)। शिक्षा विभाग के बजट में साइकिल, पोशाक और कन्या उत्थान जैसी योजनाओं का बड़ा हिस्सा है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह आवंटन अक्सर "कल्याणकारी" (Welfare) योजनाओं तक सीमित रहता है और "सशक्तिकरण" (Empowerment) या बुनियादी ढाँचे (जैसे - महिला हॉस्टल, कौशल विकास केंद्र) पर कम खर्च होता है (Barman & Gupta, 2025; Government of Bihar, Finance Department, 2024)।

शिक्षक भर्ती में आरक्षण

बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसका उद्देश्य स्कूलों में महिला रोल मॉडल की उपस्थिति बढ़ाना और लड़कियों के लिए स्कूल को एक सुरक्षित स्थान बनाना था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति ने लड़कियों के नामांकन और ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह अभिभावकों को भी आश्वस्त करता है कि उनकी बेटियाँ सुरक्षित हाथों में हैं।

सुरक्षित शनिवार (Safe Saturday) और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM)

"सुरक्षित शनिवार" कार्यक्रम, जो यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है, स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का एक अनूठा प्रयास है। हर शनिवार को बच्चों को आपदा प्रबंधन (बाढ़, भूकंप) और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में सिखाया जाता है।

- माहवारी पर चुप्पी तोड़ना: इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माहवारी स्वच्छता पर खुली चर्चा है। "किशोरी मंच" और "मीना मंच" के माध्यम से, लड़कियों को माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझने में मदद की जाती है। "मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम" के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए प्रति वर्ष ₹300 (अब राशि बढ़ाई जा रही है या पैड दिए जा रहे हैं) दिए जाते हैं।
- प्रभाव: NFHS-5 के आँकड़े बताते हैं कि 15-24 वर्ष की महिलाओं में स्वच्छ तरीकों (जैसे-पैड) का उपयोग 2015-16 के 31% से बढ़कर 2019-21 में 59% हो गया है (Pandey, 2025)। यह व्यवहार परिवर्तन शिक्षा में उनकी निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।

टोला सेवक और तालीमी मरकज

महादलित और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए सरकार ने "टोला सेवक" (दलितों के लिए) और "तालीमी मरकज" (मुस्लिमों के लिए) स्वयंसेवकों की नियुक्ति की है। ये स्वयंसेवक उसी समुदाय से होते हैं और बच्चों को घर से स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और अभिभावकों को प्रेरित करने का काम करते हैं। यह समुदाय आधारित दृष्टिकोण समावेशन के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है, हालांकि इन सेवकों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर विवाद रहे हैं (Mishra & Kumar, 2024)।

आलोचनात्मक विश्लेषण: उपलब्धियाँ और विरोधाभास

बिहार में बालिका शिक्षा की यात्रा को "गिलास आधा भरा और आधा खाली" के रूप में देखा जा सकता है।

सफलता: मात्रात्मक विस्तार

नामांकन के मामले में बिहार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक होना इस बात का प्रमाण है कि प्रोत्साहन योजनाएँ काम कर रही हैं। सामाजिक स्तर पर, साइकिल चलाती लड़की बिहार के पुनरुत्थान का प्रतीक बन गई है।

विफलता: गुणवत्ता और रोजगार

- **सशक्तिकरण विरोधाभास (Empowerment Paradox):** बिहार में एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) गिर रही है या बहुत कम (23.9%) है (Sumanlata & Kumari, 2024)। शिक्षा लड़कियों को रोजगार के लिए तैयार नहीं कर रही है, बल्कि यह उन्हें "विवाह बाजार" में एक बेहतर उम्मीदवार बना रही है। शिक्षित लड़की के लिए अधिक दहेज की मांग या "अपने स्तर के वर की तलाश" एक नई सामाजिक समस्या बन गई है।
- **सीखने का संकट:** सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियाँ अक्सर केवल उपस्थिति दर्ज कराने आती हैं (साइकिल और पैसे के लिए)। कक्षाओं में पढ़ाई का स्तर निम्न है। ट्यूशन और कोचिंग पर निर्भरता बढ़ गई है, जिसे गरीब परिवार (विशेषकर लड़कियों के लिए) वहन नहीं कर सकते।

  कार्यान्वयन की बाधाएँ

  योजनाओं का लाभ समय पर न मिलना सबसे बड़ी बाधा है। यदि कन्या उत्थान की राशि शादी के बाद मिलती है, तो वह बाल विवाह रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं करती। भ्रष्टाचार, हालांकि DBT से कम हुआ है, लेकिन निचले स्तर पर डेटा एंट्री और सत्यापन में अभी भी मौजूद है।

निष्कर्ष और भविष्य की राह

बिहार में बालिका शिक्षा की स्थिति में पिछले दो दशकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। राज्य सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और नवीन योजनाओं ने लड़कियों को हाशिए से उठाकर स्कूल के प्रांगण तक पहुँचाया है। "साइकिल" और "यूनिफॉर्म" ने उन्हें दृश्यता दी है, और "छात्रवृत्ति" ने उन्हें एक अधिकार/सहयोग दिया है।

तथापि, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अभी भी दूर है। एक महादलित लड़की, एक मुस्लिम लड़की, या एक दिव्यांग लड़की के लिए चुनौतियाँ अभी भी विकराल हैं। बुनियादी ढाँचे की कमी, शिक्षकों की गुणवत्ता, और पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड उनकी राह में रोड़े हैं।

सुझाव और सिफारिशें:

1. **लक्षित दृष्टिकोण (Targeted Approach):** "वन साइज फिट्स ऑल" (One size fits all) के बजाय, महादलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ अपनानी होंगी। मुसहर टोलों में "सेटेलाइट स्कूल" या "ब्रिज कोर्स" आवश्यक हैं।
2. **गुणवत्ता पर जोर:** अब ध्यान "नामांकन" से हटाकर "सीखने के परिणामों" (Learning Outcomes) पर केंद्रित करना होगा। उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Classes) और शिक्षक जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी।
3. **डिजिटल समावेशन:** लड़कियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए विशेष अभियान (जैसे-डिजिटल बेटी) चलाने होंगे। स्कूलों में कंप्यूटर लैब की उपलब्धता और लड़कियों द्वारा उनके उपयोग को अनिवार्य बनाना होगा।
4. **प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया को स्वचालित और समयबद्ध (Time-bound) बनाना होगा। "शिक्षा के अधिकार" की तरह "समय पर भुगतान के अधिकार" को भी लागू करना चाहिए।
5. **सामाजिक व्यवहार परिवर्तन:** शिक्षा को रोजगार से जोड़ना होगा। लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।

अंततः, बिहार की प्रगति का मार्ग उसकी बेटियों के स्कूल बैग से होकर गुजरता है। जब तक राज्य की अंतिम पंक्ति में खड़ी लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर नहीं मिलते, तब तक "विकसित बिहार" का सपना अधूरा रहेगा।

संदर्भ (References)

1. ASER. (2022). Annual Status of Education Report, Bihar. https://www.drishtiias.com/statepcs/19-01-2023/bihar/print
2. Aasha Khosa. (2025, November 8). Bihar Polls Muslim women s struggle for basics lost in din of campaigning. Https://Www.awazthevoice.in; Awaz the Voice. https://www.awazthevoice.in/women-news/bihar-polls-ignored-stories-of-muslim-women-s-struggle-for-basics-43530.html
3. Baig, A. (2024, January 23). ASER 2023 uncovers alarming gaps in rural youth education, digital access, skills; experts suggest remedial measures - India Tomorrow. India Tomorrow. https://indiatomorrow.net/2024/01/23/aser-2023-uncovers-alarming-gaps-in-rural-youth-education-digital-access-skills-experts-suggest-remedial-measures/
4. Barman, K., & Gupta, I. (2025). Gender budgeting in the post-pandemic period: an analysis in the context of health and safety of women in India. Frontiers in Public Health, 13, 1654318–1654318. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1654318
5. Bhattacharjea, S. (2024). What ASER 2023 reveals about the gender gap in confidence. Ideasforindia.in. https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/what-aser-2023-reveals-about-the-gender-gap-in-confidence
6. Bihar's School of Shame: 200 Kids, 2 Rooms, No Water, No Toilets. (2025, November 3). India Today. https://www.indiatoday.in/india/video/bihars-school-of-shame-200-kids-2-rooms-no-water-no-toilets-ytvd-2812887-2025-11-03

7. Deeksha, J. (2023, September 20). Can cash replace textbooks? Lessons from Bihar. Scroll.in. https://scroll.in/article/1056216/can-cash-replace-textbooks-lessons-from-bihar
8. Fatima, N. (2024, October 28). Early Marriage, Tradition and Safety: Unravelling the Challenges for Muslim Girls in Education. TwoCircles.net. https://twocircles.net/2024oct28/450653.html
9. Government of Bihar, Finance Department. (2024). Gender Budget 2024-25. https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/gbdocuments/17107782611749468962.pdf
10. IIPS. (2021). NFHS-5, Ministry of Health and Family Welfare Fact Sheets, KEY INDICATORS. https://mohfw.gov.in/sites/default/files/NFHS-5_Phase-I.pdf
11. Jayshree Bajoria. (2014, April 22). "They Say We're Dirty." Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2014/04/22/they-say-were-dirty/denying-education-indias-marginalized
12. Jha, D. (2021). Gross enrollment ratio. Scribd. https://www.scribd.com/document/818380123/Gross-enrollment-ratio
13. Kalaiselven, S., & Maheswari, K. (2014). A Study on Exclusion and Inclusion of Dalits in Education. Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 19(5), 39-41. www.iosrjournals.org
14. Mishra, N., & Kumar, S. (2024). An Analysis of Social Exclusion and Educational Deprivation of Mahadalits in Bihar: Challenges and Prospects. Ideal Research Review, 79(I). https://journalirr.com/wp-content/uploads/2024/09/Nisha-Mishra-14.pdf
15. MKUY. (2025, September 8). Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana 2025 – ₹50,000 Apply Online, Last Date - मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना. Kanyautthanyojana.org. https://kanyautthanyojana.org/
16. Muralidharan, K., & Prakash, N. (2017). Cycling to School: Increasing Secondary School Enrollment for Girls in India. American Economic Journal Applied Economics, 9(3), 321–350. https://doi.org/10.1257/app.20160004
17. NHSRC. (2021). HEALTH DOSSIER 2021, Bihar. https://nhsrcindia.org/sites/default/files/practice_image/HealthDossier2021/Bihar.pdf
18. NITI, A. (2025). Summary Report for the State of Bihar. https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-07/Summary-Report-Bihar%20%281%29.pdf
19. PAB minutes, (2025). Minutes of the Meeting of Project Approval Meeting (PAB) of State of Bihar Samagra Shiksha for FY 2025-26. Government of India, Ministry of

Education, Department of School Education & Literacy. https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/pab/BR_PAB_2025_26.pdf

20. Pandey, J. (2025, May 27). Menstrual health central to vision of equitable Bihar, says Bandana Preyashi. The Times of India; The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/menstrual-health-central-to-vision-of-equitable-bihar-bandana/articleshow/121442776.cms
21. Pandey, V., Pawar, S., & Prakash, N. (2025, March 14). Pedalling towards gender equality and empowerment. VoxDev. https://voxdev.org/topic/education/pedalling-towards-gender-equality-and-empowerment
22. Parmar, J., Kumari, H., Prasad, G., & Salahuddin, Mohd. (2025). Literacy rate analysis of Bihar. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(5). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i05.56968
23. Reddy, S. (2021, August 18). Mukhyamantri Kanya Utthaan Yojana. Vikaspedia.in; Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). https://en.vikaspedia.in/viewcontent/schemesall/state-specific-schemes/welfare-schemes-of-bihar/mukhyamantri-kanya-utthaan-yojana--mkuy-
24. Ratan, A., & Tiwari, A. (2025). WASH Facilities and Menstrual Hygiene Management at Schools of Rural Bihar: A Mixed-Methods Study of Adolescent Girls. South India Journal of Social Sciences, 23(1), 187–196. https://doi.org/10.62656/sijss.v23i1.1800
25. Sharma, S. (2025, October 12). Why Bihar's education system needs to be on the ballot this election: Dropout rates, inequality, and a failing future. The Times of India; The Times Of India. https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/why-bihars-education-system-needs-to-be-on-the-ballot-this-election-dropout-rates-inequality-and-a-failing-future/articleshow/124501349.cms
26. Singh, R., Saberwal, R., Mukherjee, P., & Ubale, P. (2025) 'What Drives Changes in Child Labour and Schooling? Summary of findings from an exploratory study among children of the Musahar Community in Vaishali, Bihar, India' Research Brief, Young Lives India and UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, New Delhi and Florence, May 2025.
27. Sumanlata, & Kumari, P. (2024). Gender Budgeting: An Initiative to Achieve Gender Equality. Ideal Research Review 79(1).
28. Thakore, D. (2025, February 15). UDISE+ 2023-24 Dire condition of world's largest child population. Education World. https://educationworld.in/udise-2023-24-dire-condition-of-worlds-largest-child-population/
29. Yesmin, S., & Roy, P. (2024). EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF MUSLIM GIRLS AND THEIR PROBLEMS ATHIGHER SECONDARY LEVEL IN WEST

BENGAL. The Social Science Review A Multidisciplinary Journal. March-April, 2024. 2(2). 53-62. www.tssreview.in